International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Jan-Feb- 2019, Volume-6, Issue-1 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

बी. पी.एल परिवारो के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का अध्ययन (दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में)

Harsha Kharol
Research ScholarJRNRVU

Suman Pamecha
Assistant Professor JRNRVU

सार–

वित्त धन का विज्ञान है जिस पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। वित्त अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर पाया जाता है, यह व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत वित्त के रूप में मौजूद होता है जो किसी व्यक्ति के धन प्रबंधन से संबंधित होता है, कॉर्पोरेट वित्त जो कॉर्पोरेट की फंडिंग और पूंजी संरचना से संबंधित होता है, इसमें व्यवसायों का मूल्यांकन भी शामिल होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी हर स्तर पर आवश्यकता होती है। ऐसा देखा जाता है कि अगर देश की आबादी वित्तीय पहलुओं और वित्तीय ज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जागरूक हो, तो अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा में सरकारी नीतियां और कार्यक्रम शामिल हैं जो कुशल श्रम बाजारों को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करने, लोगों के जोखिमों को कम करने और आर्थिक और सामाजिक जोखिमों को प्रबंधित करने की लोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हाल ही में, कई सरकारों ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को अपने एजेंडे में रखा है। सामाजिक सुरक्षा उपायों के राजकोषीय निहितार्थों पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है, लेकिन उत्पादन, रोजगार, आय और राजस्व प्रभावों के संदर्भ में आर्थिक प्रभावों पर नहीं। भारत सरकार वित्तीय समावेशन के महत्व को समझती है और यह समय की मांग है क्योंकि वित्तीय लेनदेन में उपयोग की जाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ इंजीनियर उत्पाद और सेवाओं के साथ वित्तीय उद्योग को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए जनसंख्या की वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है ताकि वे इस अग्रिम वित्तीय का उपयोग कर सकें। सेवाएं कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से ताकि वित्तीय वृद्धि और सामाजिक विकास कई गुना बढ़ जाए

कुंजीशब्दः *गरीबी रेखा से नीचे, सरकार के सामाजिक कार्यक्रम, गरीबी, स्वास्थ्य।*

परिचयः

आर्थिक असमानताओं से जूझ रहे विश्व में गरीबी एक गंभीर वैश्विक मुद्दा बनी हुई है। गरीबी के इस विशाल दायरे में, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द बीपीएल है, जिसका अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे। बीपीएल का तात्पर्य एक विशिष्ट आय सीमा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों या परिवारों से है, जो अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करने की उनकी सीमित क्षमता को दर्शाती है। इस शोध का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सामने आने

वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना और इन व्यक्तियों और समुदायों के उत्थान के लिए संभावित समाधान तलाशना है। विकास को किसी समाज द्वारा एक निश्चित समयावधि में शामिल किए गए सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों से भी मापा जा सकता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि और वित्तीय एवं आर्थिक विकास को किसी देश की आबादी के उत्थान और परिवर्तित जीवनशैली और आदतों में देखा जाता है। वित्तीय साक्षरता के साथ–साथ वित्तीय समावेशन वह है जहां व्यक्ति और व्यवसाय को उन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच मिलती है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है।

सतत विकास और ऊंचे जीवन स्तर के लिए किसी देश के लिए व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट स्तर पर आबादी को वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। पूंजी के उचित संचलन और अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए अर्थव्यवस्था के सतत विकास और वृद्धि के लिए इसकी वित्तीय प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति और व्यवसाय को शामिल करना आवश्यक है। इसलिए वित्तीय साक्षरता हर देश के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था का विकास उसी पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है; यह निवेश, बीमा, बचत, खर्च, सेवानिवृत्ति योजना, कर योजना के बारे में उचित निर्णय लेने के बारे में ज्ञान प्रदान करने का तरीका है। इसमें वित्तीय मध्यस्थों, वित्तीय सेवाओं का ज्ञान और कड़ी मेहनत से अर्जित धन का प्रबंधन करते समय सुरक्षा को अधिकतम करने और संबंधित वित्तीय और परिचालन जोखिमों को कम करने के लिए इनका कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए, इसका ज्ञान भी शामिल है।

वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। किसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से किफायती लेनदेन में योगदान देता है। एक अर्थव्यवस्था जनसंख्या की आय और वे अपने व्यय और बचत का प्रबंधन कैसे करते हैं, इस पर आधारित होती है। यदि इन बचतों को अधिक आय उत्पन्न करने के लिए निवेश किया जाए तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि जनता को उपलब्ध वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के बारे में जानकारी देकर बुनियादी स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत की वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। इसलिए भारत को वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है, यह कम आय वर्ग के लिए किफायती लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, इसलिए वित्तीय समावेशन समाज के आय समूहों के बीच अंतर को भी पाटता है।

स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता और खराब आर्थिक स्थिति गरीबों को दयनीय स्थिति में छोड़ देती है। गरीबी न केवल परिवारों को आर्थिक रूप से पीछे खींचती है बल्कि इसका प्रभाव उनकी सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी का बुरा असर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं पर भी पड़ता है। सरकार ग्रामीण गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में काफी पैसा खर्च कर रही है लेकिन फिर भी वह प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई कारणों से गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पाते

हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता न होने और सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण कई ग्रामीण परिवार स्वास्थ्य पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। ग्रामीण लोगों के खराब स्वास्थ्य का कारण नशा भी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई कारणों से गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

बीपीएल, जिसका अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे, भारत सरकार द्वारा उन व्यक्तियों या परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बेंचमार्क है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें मदद की आवश्यकता है। सरकार उनकी बुनियादी भोजन, आश्रय और कपड़ों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम लागू करती है। बीपीएल की अवधारणा विभिन्न देशों में भिन्न–भिन्न है, क्योंकि गरीबी के स्तर को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक देश के अपने मानदंड और सीमाएं हैं। आम तौर पर, बीपीएल को आय की कमी की विशेषता है जो व्यक्तियों और परिवारों को भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कपड़े जैसी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोकती है। अवसरों तक सीमित पहुंच के कारण ये लोग अक्सर खुद को अभाव के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं और गरीबी से बचने के लिए संघर्ष करते हैं।

निम्नांकित घटक जो बीपीएल को परिभाषित करते हैं

1. निवास का प्रकार
2. बच्चों की स्थिति
3. उपभोक्ता उत्पाद
4. खाद्य सुरक्षा
5. वस्त्र
6. साक्षरता
7. भूमि स्वामित्व
8. स्वच्छता, आदि।

बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) की विशेषताएं:

- **गरीबी रेखा की परिभाषा–** भारतीय संदर्भ में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की अवधारणा एक गतिशील गरीबी सीमा के इर्द–गिर्द घूमती है, जो बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी हासिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यय का प्रतिनिधित्व करती है। यह बेंचमार्क पूर्ण नहीं है, लेकिन यह प्रचलित मूल्य स्तर, आय वितरण और सामाजिक मानदंडों के अनुसार बदलता रहता है। इसका आकलन करने के लिए,

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) समय–समय पर घरेलू उपभोग पैटर्न को ज्ञात करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करता है, जो गरीबी रेखा के अनुमान का आधार बनता है।

- **गरीबी संकेतक:** बीपीएल वर्गीकरण केवल आय या उपभोग–आधारित गरीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरीबी की एक श्रृंखला शामिल है जो सीधे तौर पर गरीब आबादी की भलाई को प्रभावित करती है। भूमि के स्वामित्व, आवास के प्रकार, कपड़े, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं तक पहुंच, साक्षरता की स्थिति, श्रम भागीदारी, आजीविका के स्रोत, बाल कल्याण, ऋणग्रस्तता की स्थिति प्रवासन के कारणों सहित कई संकेतकों को अलग–अलग भार और स्कोर दिए गए हैं। परिवारों द्वारा अनुभव किए गए अभाव की सीमा को रेखांकित करना।

- **गरीबी उन्मूलन योजनाएं:** मुख्य रूप से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न गरीबी–विरोधी पहलों के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, बीपीएल महत्वपूर्ण कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें उल्लेखनीय हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)।

- **गरीबी मूल्यांकन और निगरानी:** इसके अलावा, सरकार गरीबी को कम करने और हाशिये पर पड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए बीपीएल समंक पर निर्भर करती है। बहुसंख्यकों में तीक्ष्णता और विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक स्तरों में गरीबी के वितरण की पेशकश करके, बीपीएल अनुमान गरीबी–विरोधी हस्तक्षेपों की दक्षता और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है, जिससे साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण और निगरानी की सुविधा मिलती है।

बीपीएल कार्ड के फायदे:

इन परिवारों की सही पहचान करने और उनके समर्थन और उत्थान के लिए वित्तीय और गैर–वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बीपीएल कार्ड देती है। बीपीएल कार्ड होने के कई फायदे हैं:

- **सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच:** बीपीएल कार्ड वाले व्यक्ति या परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों के हकदार हैं, जैसे कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न, शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल। ये योजनाएं गरीबी को कम करने और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद कर सकती हैं। कम आय वाले परिवारों के बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सकते हैं, और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लोग राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी के माध्यम से 100 दिनों की गारंटीशुदा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, गरीबी स्तर से नीचे रहने वाले लोगों को आरएसबीवाई के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच प्रदान की जाती है।

- **सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर:** बीपीएल परिवारों को आवास योजनाओं, बिजली सब्सिडी और रोजगार के अवसरों जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सुविधा प्राथमिकता तक पहुंच दी जाती है। इससे उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

- **आवश्यक सेवाओं तक पहुंच**: सरकार इस समूह के लोगों को विशिष्ट अनुदान, छात्रवृत्ति और सरकारी पदों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, यह वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोगों को उद्यमिता में प्रशिक्षित करने के लिए कई आय–सृजन पहल चलाता है।

सामाजिक आर्थिक कारक:

सामाजिक अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है कि आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं और उन्हें आकार देती हैं। यह स्थानीय या क्षेत्रीय या वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण समाज की प्रगति, ठहराव या गिरावट का विश्लेषण करता है। ये कारक जीवनशैली के घटक और वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक स्थिति दोनों के माप हैं। वे सीधे सामाजिक विशेषाधिकार और वित्तीय स्वतंत्रता के स्तर को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य स्थिति, आय, पर्यावरण और शिक्षा जैसे कारकों का अध्ययन समाजवादियों द्वारा इस संदर्भ में किया जाता है कि वे मानव व्यवहार और परिस्थितियों को कैसे प्रभावित करते हैं। जीवनशैली माप के रूप में, माना जाता है कि उनका मानव आबादी में नशीली दवाओं के उपयोग, भोजन विकल्पों, प्रवासन, बीमारी की व्यापकता और मृत्यु दर के पैटर्न से सीधा संबंध है। इन कारकों में शामिल हैं।

शिक्षा या साक्षरता का स्तर: शिक्षा का स्तर सामाजिक आर्थिक विकास को मापने का सबसे स्पष्ट तरीका है क्योंकि उच्च शिक्षा जनसंख्या की आय और विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाती है।

- आय और संपत्ति: परिवार का एक व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, इसमें शुद्ध आय का प्रत्यक्ष योगदान होता है। आय विकल्पों और रहने की स्थितियों को निर्धारित करती है।

- स्वास्थ्य और जीवनशैली: स्वास्थ्य स्थिति सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक निश्चित माप है। आनुवंशिक रूप से खराब स्वास्थ्य, मौसम, पूर्ववृत्ति, दुर्घटना या जीवनशैली विकल्प। यह गतिशीलता और सामाजिककरण की क्षमता को प्रभावित करता है। कुछ स्थितियों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और दवा पर निर्भर जीवनशैली द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, जो बहुत महंगा हो सकता है।

- पड़ोस की गुणवत्ताः पर्यावरण को सामाजिक आर्थिक स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह इसका प्रतिबिंब है। यह व्यक्तियों के पड़ोस और रहने की स्थिति है और आसपास वे किराए पर या स्वयं के स्वामित्व वाले घर या फ्लैट या बंगले आदि में रहते हैं।

- सामाजिक मुद्देः समाज के सामाजिक मुद्दे, उदाहरण के लिए महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, बाल श्रम, आदि।

बीपीएल परिवारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी निम्न प्रकार से है।

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की, जिसके बाद इस योजना का कार्य 24 अगस्त 2014 से शुरू किया गया जिसके तहत अब तक लगभग 11 करोड़ खाते खोले गए है। इस योजना के अन्तर्गत खाताधारको को 30,000/– न्यून्तमक राषि का जीवन बीमा दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से, उन्हें किफायती दरों पर बचत और जमा खाते, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, भुगतान आदि जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिलती है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 29.43 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं।

फ़ायदे:-

- 26 जनवरी 2014 से पहले बैंक खाते खोलने वालों के लिए, सरकार 1 लाख से अधिक के लिए दुर्घटना बीमा कवर और 10 लाख रुपये से अधिक के लिए बीमा कवर देने की योजना बना रही है। 30,000/– न्यूनतम बीमा राषि प्रदान की गई।

- धन जमा पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

- मिनिमम बैलेंस का कोई नियम नहीं होगा।

- भारत में किसी भी बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, साथ ही किसी सरकारी योजना का पैसा सीधे किसी व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।

- रुपये तक 6 महीने तक बैंक खाता चलाने पर 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है।

2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाः

इस योजना की घोषणा 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने की थी। यह एक साल की नवीकरणीय जीवन बीमा योजना है जो रुपये का जीवन कवरेज प्रदान करती है। वार्षिक प्रीमियम के साथ 2 लाख रु. 330 जो योजना के नवीनीकरण के समय देय है। दिया गया प्रीमियम खाताधारक के बचत खाते से ऑटो–डेबिट सुविधा के माध्यम से काट लिया जाएगा। इसका लाभ कोई भी बचत बैंक खाताधारक उठा सकता है

जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा, एक बार खाताधारक 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो उसका बीमा समाप्त कर दिया जाएगा।

फ़ायदे:

- नामांकित व्यक्ति मृत्यु लाभ प्राप्त कर सकता है।
- यह एक साल का कवर है यानी 1 जून से 31 मई तक।

3. सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत् सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक बालिका की शिक्षा और शादी के खर्च को पूरा करना है। इस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान लड़की के बैंक खाते में न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा, खाता तभी बंद किया जा सकता है जब लड़की 21 वर्ष की हो जाए यदि खाता बंद नहीं किया गया है तो धारक अभी भी राशि पर ब्याज अर्जित कर सकता है।

फ़ायदेः

- जैसे ही लड़की 10 वर्ष की हो जाए, उसके माता–पिता या अभिभावक यह खाता खुलवाते है व संचालित कर सकते है।
- आयकर लाभ के साथ 8.6% की ब्याज दर उपलब्ध करवाई जाती है।
- किसी लड़की की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके 18 वर्ष की होने के बाद शेष राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। इसके अलावा, धन को एक अधिकृत बैंक से दूसरे में भी स्थानांतरित किया जा सकता है और इसके विपरीत भी।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)

आरएसबीवाई को वर्ष 2008 में उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रचलित किया गया था जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित हैं। चूँकि यह असंगठित क्षेत्र को स्वास्थ्य पर बीमा कवरेज प्रदान करता है जो सड़क विक्रेताओं, लाइसेंस प्राप्त कुलियों, कल्याण बोर्डों आदि के तहत पंजीकृत है।

फ़ायदे:

- 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए, यह फ्लोटर आधार पर 30,000/– रुपये तक का कवर देता है।

- रुपये की अधिकतम सीमा के साथ. 1,000/– रुपये का परिवहन शुल्क कवर प्रदान करता है। अस्पताल में प्रति विजिट 100/–रुपये

- आरएसबीवाई स्मार्ट कार्ड बीपीएल परिवारों को प्रदान किया जाता है जो धारकों को रुपये तक की चिकित्सा देखभाल खर्च का दावा करने की अनुमति देता है। मात्र 30 रुपये के प्रीमियम के साथ 3000 प्रति वर्ष।

5. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY)

ABPMJAY को दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना के रूप में प्रचारित किया जाता है, जिसे दस करोड़ गरीब परिवारों को कवर करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं वाले परिवार, भिखारी, घरेलू मदद, निर्माण श्रमिक, स्वच्छता कार्यकर्ता, सार्वजनिक परिवहन चालक आदि शामिल हैं। और ग्रामीण क्षेत्र. यह प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है।

फायदेः

- इस योजना के तहत जरूरत के समय सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी और सार्वजनिक दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा।
- परिवारों की आयु और आकार पर कोई सीमा नहीं होगी।
- यह अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के दोनों खर्चों को कवर करता है।

भारत में बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। सरकार ने इन परिवारों को समर्थन देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, और ऐसी ही एक पहल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड है। बीपीएल कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे है, और यह कार्डधारकों को कई लाभ प्रदान करता है।

बीपीएल कार्ड के फायदेंः

1. खाद्य सब्सिडीः बीपीएल कार्डधारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्य सब्सिडी के हकदार हैं। सरकार पीडीएस दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित करता है कि बीपीएल परिवारों को सस्ती कीमतों पर बुनियादी खाद्य पदार्थों तक पहुंच प्राप्त हो।

2. स्वास्थ्य लाभः बीपीएल कार्डधारक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वे सरकारी औषधालयों में सामान्य बीमारियों के लिए मुफ्त दवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराते हैं।

3. शिक्षा लाभः बीपीएल परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में मुफ्त स्कूल वर्दी, पाठ्यपुस्तकें और मध्याह्न भोजन जैसे शिक्षा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता का भी लाभ उठा सकते हैं।

4. आवास लाभः बीपीएल परिवार आवास लाभ का लाभ उठा सकते हैं जैसे घर बनाने के लिए सब्सिडी वाले ऋण, किफायती आवास योजनाओं तक पहुंच और झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास योजनाएं।

5. रोजगार लाभः बीपीएल परिवार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौकरी प्लेसमेंट और स्वरोजगार योजनाओं जैसे रोजगार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये पहल बीपीएल परिवारों को आजीविका कमाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं।

बीपीएल कार्ड धारकों के लिए निम्न 5 बीमा योजनाऐं उपलब्ध है।

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है। यह असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए लक्षित है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वार्षिक प्रीमियम रु. सरकार द्वारा 750/– रुपये का भुगतान किया जाता है। बीमाधारक को सिर्फ रुपये का भुगतान करना होगा। योजना को नवीनीकृत करने के लिए सालाना 50/– निर्धारित है।

2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना–

यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गई है। यह आकस्मिक मृत्यु कवर, मातृत्व कवर और आय की हानि प्रदान करता है – जो सभी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इसके प्रीमियम पर सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है।

3. मुख्यमंत्री अमृतम योजना–

मुख्यमंत्री अमृतम योजना गुजरात राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली एक योजना है। इसका गंभीर बीमारी कवर आपको कैंसर के इलाज, अंग प्रत्यारोपण आदि की लागत को कवर करने में मदद करता है।

4. करुण्य स्वास्थ्य बीमा योजना–

करुणा स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य गंभीर सशक्त से पीड़ित लोगों को प्रदान करना है। इस योजना पर आवश्यक बीमा राशि वृद्धि का विकल्प भी उपलब्ध है।

5. आयुष्मान भारत योजना–

आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को कैशलेस बनाती है। यह व्यापक कवरेज प्रदान करता है जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद की लागत शामिल है।

उद्देश्य:

- गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बारे में अध्ययन करना
- सरकारी योजनाओं से परिवारों को हुए लाभ के बारे में अध्ययन करना।
- सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रमों से बी.पी.एल परिवारों की सामाजिक स्थिति पर हुए प्रभाव का अध्ययन।
- बी.पी.एल परिवारो के लिए सरकार की भावी योजनाओं का अध्ययन करना।

शोध विधि–

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार समंको के माध्यम से किया गया। समक संग्रहण हेतु निम्न विधियों का उपयोग किया गया–

- प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा
- अनुसूचियों के माध्यम से
- संकलित तथ्यों का अन्वेषण करके
- वार्षिक प्रतिवेदनों के अध्ययन माध्यम से
- विभिन्न संस्थाओं की नियम सम्बंधी पत्रावलियों के माध्यम से।

निष्कर्ष:

शिक्षा, लिंग संबंधी समस्याएं, रोजगार से जुड़े मुद्दे और साथ ही धार्मिक कारकों को गरीबी के मुख्य कारक माना जा सकता है। इस प्रकार, 2000 में आय/खाद्य आवश्यकताओं के अनुसार गरीबी रेखा तय की गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे न केवल अपने नागरिकों को मदद मिली बल्कि उनकी वित्तीय स्थितियों में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को कई लाभ प्रदान करता है। यह योजना सुनिश्चित करती

है कि बीपीएल परिवारों को आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास और रोजगार के अवसरों तक पहुंच हो। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचे। सरकार और नागरिक समाज को बीपीएल परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजना में कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लंबे समय से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों ने सोचा है कि स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उनकी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इन मिथकों को तोड़ा जाए। रियायती प्रीमियम वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं जो यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति के बावजूद आपको उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त हो। कई बीपीएल स्वास्थ्य बीमा योजनाएं वास्तव में बीपीएल कार्ड के अन्य लाभों तक पहुंच के साथ–साथ तनावपूर्ण वित्तीय स्वास्थ्य वाले परिवारों को चिकित्सा आपातकाल से बेहतर ढंग से निपटने में मदद कर सकती हैं।

संदर्भः

1. अग्रवाल, के, वी, डॉ. (2014) भारत में वित्तीय समावेशनरू एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। वाणिज्य व्यवसाय और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।

2. अरुण, टी., और कामथ, आर. (2015) वित्तीय समावेशनरू नीतियां और प्रथाएं। आईआईएमबी प्रबंधन समीक्षा।

3. अग्रवाल, एम.आर. (2017) वित्तीय प्रबंधनरू जयपुररू गरिमा प्रकाशन।

4. भट्ट, के.ए., डॉ. (2013) शेयर बाजार में कारोबार करने वाले व्यक्तियों का निवेश और ट्रेडिंग पैटर्न। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जर्नल्स।

5. बंसल, एस., (2014) ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी का परिप्रेक्ष्य। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन

6. बीना, सी, ए. और साड़ी, टी, सी. (2014) कुदुंबश्री के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन – भारत के केरल राज्य के त्रिशूर निगम का एक अध्ययन। दृश्य.

7. बाबू, पी. आर., डॉ. (2015)। कृष्णा जिलेरू आंध्र प्रदेश में ग्रामीण परिवारों के बीच वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के स्तर का विश्लेषण। इसरो जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस।

8. बरुआ, ए., कथूरिया, आर., और मलिक, एन., (2016)। भारत में वित्तीय समावेशन, विनियमन और शिक्षा की स्थिति।

9. बेरवाल, आर., और बेरवाल, एम. (2017)। भारत में वित्तीय समावेशनरू आरबीआई की भूमिका। वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रकाशनों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।

10. चक्रवर्ती, एस., और डिगल, एस.के. (2011)। व्यक्तिगत परिवारों के बचत और निवेश व्यवहार का एक अध्ययन – उड़ीसा से एक अनुभवजन्य साक्ष्य। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल।

11. दास, एम., और चार्ल्स, सी. (2009)। भारत में बैंकों की तकनीकी दक्षता का एक अध्ययन। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल।

12. कल्ल, आर., कुंट, डी, ए., और लाइमैन, टी., (2012) वित्तीय समावेशन और स्थिरतारू अनुसंधान क्या दिखाता है। सीजीएपी प्रकाशन।